

EASTERN RAILWAY

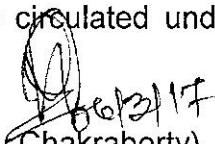
No. E.66/0/Pt. I

Kolkata, dated 06th March, 2017.

All Concerned.

Sub:- Grant of Transport Allowance at double the normal rates to deaf and dumb Employees of Railways.

The following Copy of Railway Board's letter No. PC-V/2014/A/TA/1 dated 22.02.2017 (RBE No. 14/2017, S. No. PC-VI/374) on the above mentioned subject is forwarded for information guidance and necessary action. Board's earlier letters dated 19.03.2014, 12.09.2008 and 23.10.1978 mentioned therein were circulated under this office serial circular Nos. 27/2014, 97/2008 and 17/79 respectively.


(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/BGB
for Chief Personnel Officer

Copy of Board's letter No. . PC-V/2014/A/TA/1 dated 22.02.2017 (RBE No. 14/2017, S. No. PC-VI/374) addressed to GMs, All Indian Railways and others.

Sub:- Grant of Transport Allowance at double the normal rates to deaf and dumb Employees of Railways.

In supersession of Railway Board's letter of even number dt. 19.03.2014 (RBE No. 28/2014) regarding admissibility of Transport Allowance at double the normal rates to employees who are deaf and dumb, it is stated that the matter has been re-examined and it has been decided with the approval of Competent Authority that Transport Allowance at double the normal rates is admissible to Hearing Impaired employees also in addition to employees who are both deaf and Dumb.

2. Transport Allowance at double the normal rates would be admissible to the 'Hearing Impaired employees having loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversation range of frequencies' as per Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

3. The admissibility of Transport Allowance at double the normal rates to above categories of employees is subject to recommendation of the Head of ENT Department of a Railway or Government Civil Hospital and fulfillment of other conditions applicable in respect of other disabilities mentioned in Railway Board's letter No. F(E)I-78/AL-7/5 dated 23.10.1978 read with Board's letter dated 12.09.2008 (RBE No. 111/2008).

4. These orders would be effective from 19.02.2014.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

.....
Index No. 1057: Transport Allowance at double the Normal Rates to Hearing Impaired employees in addition to employees who are both deaf and Dumb.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 14/2017

क्र.सं. पीसी-VI/374

सं.पीसी-V/2014/ए/टीए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे के मूक और बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दरों पर परिवहन भत्ता प्रदान करना।

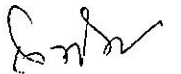
रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.03.2014 (आरबीई नं. 28/2014) के समसंख्यक पत्र, जो मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में है, के अधिक्रमण में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की फिर से जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि उन कर्मचारियों को जो मूक एवं बधिर दोनों हैं, के अतिरिक्त कम श्रवण शक्ति वाले कर्मचारियों को भी सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय है।

2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार 'उन कम सुनने वाले व्यक्तियों जिनके कम खराब कान में वार्तालाप के रेंज की फ्रीक्वेन्सी (conversation range of frequencies) के भीतर सुनने में 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो, को सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

3. रेलवे अथवा सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के हेड की सिफारिश पर और रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.10.1978 के पत्र सं. एफ(ई)।-78/एएल-7/5 जिसे बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 (आरबीई सं. 111/2008) के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, में उल्लिखित अन्य लागू शर्तों के पूरा करने पर ही, उपर्युक्त कोटियों के कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

4. यह आदेश 19.02.2014 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V

रेलवे बोर्ड.

{प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 17.01.2017 का कार्यालय जापन सं. 20/2/2016-ई.।।(बी)}